सक्षम विद्यार्थियों को अग्रिम पढ़ाई के लिए दाखिले देने से इन्कार कर देने के समाचार को देख कर हृदय अति दुखित हुआ । देश एक ओर कृषि विकास, औद्योगिक विकास एवं सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है और दूसरी ओर हम सक्षम विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा हेतु व्यवस्था तक न कर पायें, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में अविलम्ब उचित कदम उठाये जायें ।

(v) Directions for providing Security to Journalist.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकार समाज क दर्पण हैं जिनमे समाज का असली और नकली चेहरा सामने नजर आता है । इन चेहरों पर जो विकृतियां होती हैं उनके कारणों का पता लगाकर पत्रकार समाज के सामने उनका भंडा-फोड़ करते हैं । ये पत्रकार समाज के सामने असली चेहरा रखते हैं । वे अपने निष्पक्ष विचारों के माध्यम से सभी प्रकार के दबावों से अप्रभावित रह कर सही बातों को समाज के सामने रखते हैं । इस प्रकार सार्वजनिक हित के लिए वे रचनात्मक कार्य में संलग्न सरकारी व गैर-सरकारी स्तर पर पत्रकार अपनी सुरक्षा व सम्मान की समाज से अपेक्षा करते हैं । परन्तु, आजकल आए दिन पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है । उनकी स्वतंत्र व निष्पक्ष आवाज दबाने की कोशिश की जाती है और कई बार प्रशासनिक तंत्र उनको सुरक्षा करने में राजनीतिक दबाव के कारण असफल सिद्ध हुआ है । यह लोकतंत्र के लिए अशोभनीय बात है । समाचारपत्रों की स्वतत्रता लोकतंत्र की सजीवता व सुरक्षा के आधार स्तम्भ हैं । इसलिए पत्रकारों को अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभाने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ हो कर उनको सहायता और सहयोग देना चाहिए । ऐसा नहीं करना, लोकतांत्रिक मूल्यों, परम्पराओं स्वच्छंद पत्रकारिता तथा वैचारिक स्वतन्त्रता पर घोर आघात करना है । इसके लिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी ओर से सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को इस प्रकार के निर्देश जारी करेगी ताकि पत्रकार सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें और गुण्डे व असामाजिक तत्वों के शिकार होने से बच सकें ।

(vi) Help to drought affected people of Andhra Pradesh.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : There is severe drought in Rayalaseema and other areas of Andhra Pradesh. Even during this month there are no rains. Most of the tanks in the drought-affected areas are dry. Even the standing crops are withering out due to lack of water in the irrigation wells. There is no drinking water in many of the villages. The cattle are suffering without fodder. The poor people are without employment. It is for the authorities to come to the rescue of the villagers so as to provide at least drinking water and arrange for supply of fodder to the cattle at concessional rates so as to save cattle. Employment should also be found for the poor who are badly affected by drought. The difficulties of the people have been accentuated by the strike situation prevailing in Andhra Pradesh. It is, therefore, important that the Central Government should see that the drought affected people in Andhra Pradesh are helped in every way.

(vii) Setting up of Advisory body in districts to advise banks to grant loans under various government schemes.

श्री जैनुल बशर : (गाजीपुर) उपाध्यक्ष जी, बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु चयनित परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । पिछले दिनों मैंने अपने जिले गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इस मामले का अध्ययन किया । मैंने यह पाया कि राज्य सरकार की एजेन्सियों ने परिवारों का चयन करके सहायता हेतु बैंकों के पास विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो नाम भेजे थे उनमें बहुत कम लोगों को बैंकों द्वारा सहायता दी गई । राज्य सरकार की एजेंसियां ग्राम-प्रधानों, जन-प्रतिनिधियों आदि की राय से गरीब लोगों का नाम बैंकों के

पास सहायता के लिए भेजती हैं। परन्तु, सहायता देने के बजाय बैंक उनको अपनी तरफ से छानबीन करने के लिए बराबर दौड़ाते रहते हैं और फिर भी सहायता नहीं देते। ऐसी दोहरी व्यवस्था के कारण अधिकतर चयनित परिवार सहायता पाने से वंचित ही रहते है और दूसरी तरफ उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के सरकारी कार्यक्रम की सफलता में तब तक शंका बनी रहेगी जब तक कि बैंक इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग नहीं करेंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि राज्य सरकारों द्वारा एक सीमित रकम तक दी गई सहायता की जमानत लेने के बावजूद भी बैंक सहायता देने में आनाकानी कर रहे हैं।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस कार्य को देखने के लिए प्रत्येक जिले में एक सलाहकार समिति बनायी जाए जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता पाने वालों को बैंक से सहायता दिलाने के काम में मदद करे।

(viii) Running Sarnath Express train daily between Varansi and Durg.

श्री बी०डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी एवं दुर्ग नगरों के बीच चलती है। वाराणसी से यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन वृहस्पतिवार एव शनिवार को चलती है और उसी प्रकार दुर्ग से सप्ताह में दो दिन शुक्रवार एवं रविवार को चलती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार के दसियों हजार लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ संभाग के अन्य स्थानों पर कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ संभाग के कृषि श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में मौसमी मजदूरों के रूप में इलाहाबाद होकर अन्य स्थानों को जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस संभाग के लाखों तीर्थयात्री प्रति वर्ष प्रयाग, काशी तथा अयोध्या के तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ आते-जाते हैं। परन्तु खेद का विषय है कि छत्तीसगढ़ संभाग से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार के पश्चिमी भाग को जोड़ने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को छोड़कर कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। और सारनाथ एक्सप्रस सप्ताह में मात्र दो दिन ही चलती है, जिससे उपर्युक्त क्षेत्रों के बीच एक बहुत बड़ी संख्या में आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं गत जून माह में दुर्ग गया था तो बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात की शिकायत की थी।

अतएव मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह अनुरोध करूंगा कि सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाय।

(ix) Shifting of D.V.C. Headquarters to Bihar.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : बिहार की जनता, उपेक्षाओं के क्रम में, दामोदर घाटी निगम की उपेक्षा से बड़ी चिंतातुर हो गई है। दामोदर घाटी निगम के स्थापना काल 1964 में बिहार के तत्कालीन विद्युत मंत्री स्व० राम चरित सिंह ने बिहार के विधायकों को आश्वासन दिया था कि निगम मुख्यालय बिहार में होगा। दुर्भाग्यवश इसका मुख्यालय कलकत्ता में चला गया।

वहां जाने पर भी बिहार के क्षतिग्रस्त एवं पीड़ित किसानों की क्षतिपूर्ति घोखाधड़ी में अत्यल्प राशि देकर की गई। निगम के विधान के अनुसार उपाध्यक्ष भी बिहार से नहीं लिया गया। करीब 100,000 जनता विस्थापित हुई तथा लाखों एकड़ कृषि भूमि दामोदर नदी के जलाशयों में जलमग्न हो गई। नौकरियों में प्रभावित लोगों की घोर उपेक्षा हुई। विद्युत आपूर्ति एवं सिंचाई में नगण्य लाभ हुआ।

इस पर बिहार सरकार ने सभी दलों के 24 विधायकों की एक विद्युत परियोजना समिति विपक्षी नेता श्री सुनील मुखर्जी की अध्यक्षता में अप्रैल 73 में गठित की गई। उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार भी डी वी सी ने विद्युत आपूर्ति केन्द्रीय उपक्रमों में व्यय कर बिहार की घोर उपेक्षा की। साथ ही नियोजनों में भी 10-15 भी स्थान नहीं दिए गए।

95 प्रतिशत परियोजनाएं बिहार की धरती पर हैं तथा इसका सभी लाभ बिहार से अन्यत्र